RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com
www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

■ INDORE ■ 11 SEPTEMBER TO 17 SEPTEMBER 2019 ■ प्रति बुधवार ■ वर्ष 05 ■ अंक 3 ■ पृष्ठ 8 ■ कीमत 5 रु.

Inside News

सऊदी की पेट्रोलियम कंपनी ला रही है दुनिया का सबसे बड़ा IPO

Page 2

आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

Page 3

ऑडी इंडिया ने लांच की लिमिटेड-ऐडिशन ऑडी क्यू 7 ब्लैक ऐडिशन

Page 5

editoria!

बिगड़ते हुए शहर

अफसोस की बात है कि दुनिया के अच्छे शहरों की गिनती में हमारे शहर कहीं नहीं ठहरते बल्कि उनकी हालत और खराब हुई है। अच्छे शहरों से आशय रहने लायक शहरों से है। इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (ईआईयू) के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2019 में दिल्ली इस साल छह स्थान फिसलकर 118वें नंबर पर और मुंबई दो मुकाम नीचे आकर 119 वें नंबर पर पहुंच गया है। दिल्ली की रैंक इसलिए गिरी क्योंकि बीते एक साल में यहां अपराध और वायु प्रदूषण बढ़ा है। मुंबई को संस्कृति और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले साल से कमजोर आंका गया। ईआईयू के इस सूचकांक में शहरों को पांच प्रमुख मानदंडों के आधार पर परखा जाता है- स्थिरता, संस्कृति व पर्यावरण, हेल्थकेयर, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर। 140 देशों की इस सूची में ऑस्ट्रिया का वियना पहले नंबर पर है। शीर्ष 10 शहरों में ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तीन-तीन शहर शामिल हैं। सूची के आखिरी दस शहरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका नीचे से तीसरे यानी 138वें और पाकिस्तान का कराची 136वें नंबर पर है। यह सूचकांक हमारी विकास प्रक्रिया पर एक बड़े प्रश्नचिह्न जैसा है। आधुनिक युग में डिवेलपमेंट की एक बड़ी कसौटी शहर भी हैं। रहने लायक शहर एक देश की आर्थिक हैसियत के साथ-साथ सक्षम शासन तंत्र और उन्नत नागरिक समाज के प्रतीक भी होते हैं। अच्छे शहरीकरण के लिए यह जरूरी है कि वह योजनाबद्ध हो। उसमें नागरिकों को कामकाज की सुविधा और जीवन की तमाम सहूलियतें मिलें, जैसे बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य। आज के दौर में अच्छे स्वास्थ्य के लिए शहर का प्रदूषण मुक्त होना जरूरी है। साथ ही नागरिकों को पूर्ण सुरक्षा और अपनी मर्जी का जीवन जीने की आजादी मिलनी चाहिए। भारत में शहरीकरण अनायास और अराजक तरीके से हुआ। विकास का विकेंद्रीकरण नहीं हो सका, इसलिए लोग रोजी-रोटी के लिए बड़े शहरों की तरफ भागे। इस तरह जनसंख्या का बोझ शहरों पर बढ़ता गया। बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से तमाम व्यवस्थाएं बनती गईं लेकिन उनमें सुरुचिपूर्ण दृष्टि का अभाव रहा। जाहिर है, एक अच्छा शहर विकसित न हो पाने के पीछे विकासशील होने की मजबूरी भी काम कर रही है। पर अगर हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं और एक विकसित राष्ट्र होने का सपना देखते हैं तो हमें अपने शहरों को व्यवस्थित करना ही होगा। विदेशी पूंजी और प्रतिभा का लाभ हम तभी ले पाएंगे। अन्य देशों के छात्र, शिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ हमारे यहां आने को तभी प्रेरित होंगे। पिछले कुछ समय से स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है लेकिन अभी तक यह अवधारणाओं में ही सीमित है। इसे जमीन पर उतारने में वक्त लगेगा लेकिन अपने शहरों की हवा और माहौल सुधारने में हमें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए।

पेट्रोल-डीजल की कीमतें रोजाना तय करने से बच रहीं तेल कंपनियां

नई दिल्ली। एजेंसी

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दो साल सरकारी तेल कंपनियों ने पहले जिस उत्साह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा करने की परंपरा शुरू की थी, उससे शायद उसने खुद अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। यह हम नहीं, बल्कि इससे जुड़े आंकड़े बता रहे हैं। यहीं नहीं, चुनाव के वक्त तो कई दिनों तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जून से लेकर अगस्त तक की तीन महीने की अवधि में कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 43 दिन तथा डीजल की कीमत में 47 दिनों तक कोई बदलाव नहीं किया। बड़ी बात यह है कि जून से अगस्त की ही अवधि में डीजल की कीमत में लगातार 13 दिनों तक कोई बदलाव नहीं किया गया, जबकि पेट्रोल की कीमत में लगातार आठ दिनों तक कोई बदलाव नहीं किया गया। इसके अलावा, नौ बार डीजल की कीमतों में लगातार चार दिन या उससे अधिक दिनों तक कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं, आठ बार पेट्रोल की कीमत में लगातार चार दिन या उससे अधिक दिनों तक कोई बदलाव नहीं आया।

तेल कंपनियों ने जून 2017 से तेल की कीमतों की रोजाना समीक्षा की शुरुआत की थी। इससे पहले लगभग तीन वर्षों तक वह 15 दिनों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की समीक्षा करती थी। 18 अक्टूबर, 2014 को केंद्र सरकार ने डीजल की कीमतों पर से अपना नियंत्रण समाप्त कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इसकी कीमत बाजार से नियंत्रित (पेट्रोल की कीमतों पर से अपना नियंत्रण सरकार ने 2010 में खत्म कर दिया था) होने लगीं। जून 2017 से लेकर अब तक इन दो सालों के दौरान तेल कंपनियों ने चुनावों को छोड़कर रोजाना आधार पर तेल की कीमतों में परिवर्तन किया।

चुनावों के दौरान कंपनियों ने तेल की कीमतें स्थिर रखीं। पिछले साल कर्नाटक चुनाव से पहले पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में लगातार 20 दिनों तक कोई बदलाव नहीं हुआ। 12 मई को मतदान समाप्त होने के बाद 15 दिनों के भीतर पेट्रोल की कीमत में चार रुपये की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद, अगले दौर के विधानसभा चुनाव (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं मिजोरम) से पहले तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण सरकार को पेट्रोल तथा डीजल पर उत्पाद शुल्क में 1.5 रुपये की कटौती करनी पड़ी और उसने तेल कंपनियों को लागत में प्रति लीटर एक रुपये का नुकसान सहने को कहा। साल 2017 में 16 जनवरी से लेकर एक अप्रैल तक तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस समय पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर में चुनाव होने थे।

40 लाख छोटे कारोबारियों को मिल सकता है जीएसटी से छुटकारा

नई दिल्ली। छोटे कारोबारियों (Small Traders) को सालाना गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न (Return) भरने से छूट मिल सकती है? सूत्रों के मुताबिक, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) वित्त वर्ष 2017-18 के सालाना रिटर्न भरने से राहत देने पर विचार कर रही है। अंतिम फैसला 20 सितम्बर को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में लिया जा सकता है।

40 लाख छोटे कारोबारियों को मिलेगी राहत

छोटे कारोबारियों को सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की छूट मिलने पर माथा-पच्ची से राहत मिलेगी। छोटे कारोबारियों को GSTR-9 और GSTR-9A के साथ उएऊ-9ण भी नहीं भरना होगा। 5 करोड़ रुपये तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को राहत देने पर विचार हो सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 30 से 40 लाख कारोबारियों/ट्रेडर्स को राहत मिलेगी।

सरकार के पास कारोबारियों को मासिक और तिमाही रिटर्न के आंकड़े मौजूद हैं। तकनीकी दिक्कतों के चलते इसकी अंतिम

तारीख को 30 नवंबर तक बढ़ाया गया था। अगले साल से ई-एनवॉइस लागू होने के बाद लागू सालाना रिटर्न की जरूरत नहीं।

अगस्त में 1 लाख करोड़ रुपये से कम रहा जीएसटी कलेक्शन उएऊ कलेक्शन अगस्त में 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े से नीचे 98,202 करोड़ रुपये रहा. जीएसटी कलेक्शन जुलाई में 1.02 लाख करोड़ रुपये था। हालांकि पिछले साल अगस्त के 93,960 करोड़ रुपये के जीएसटी कलेक्शन (GST Collection) के मुकाबले यह 4.5 प्रतिशत अधिक है।

कच्चे तेल में उछाल अमेरिका में स्टॉक घटने के असर

सोने की कीमतों पर दबाव-कच्चे तेल में मजबूती

नई दिल्ली। एजेंसी

बुधवार को कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखने को मिली। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट 51 सेंट या 0.60 फीसदी की तेजी के साथ 63 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। अमेरिका में कच्चे तेल का भंडार अनुमान से ज्यादा लुढ़क गया है। बाजार का अनुमान 27 लाख बैरल घटने का था। साथ ही अमेरिका में कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट देखने को मिली। अमेरिका में कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली रिग्स की संख्या में लगातार तीसरे हफ्ते कमी आई। सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। MCX पर इसका दाम 3 हफ्ते के निचले स्तर के करीब है। रिकॉर्ड स्तर से सोने की कीमतें करीब 1700 रुपए गिर चुकी है। COMEX पर सोने में हल्की बढ़त है लेकिन कीमतें 4 हफ्ते के निचले स्तर पर बनी हुई हैं। चांदी की कीमतों पर भी दबाव है पिछले हफ्ते के ऊपरी स्तर से दाम करीब 3 हजार रुपए गिर गए हैं।कच्चे तेल की कीमतों में आज मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रेंट के दाम 63 डॉलर के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिका में भंडार घटने की आशंका से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है।

सऊदी की पेट्रोलियम कंपनी ला रही है दुनिया का सबसे बड़ा IPO

रियाद। एजेंसी

दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी (Saudi Aramco) अरामको IPO (Initial Public Offering) लाने जा रही है। सऊदी अरब की अरामको इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आईपीओ का समय सऊदी सरकार तय करेगी। यह आईपीओ दो फेस में आएगा। सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको (Saudi Aramco) दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफे वाली कंपनी है। हाल ही में कंपनी ने पहली बार अपने फाइनेंशियल डाटा का बॉन्ड इन्वेस्टर्स के सामने खुलासा किया है। अरामको का 2018 में प्रॉफिट 111.1 अरब डॉलर रहा, जो इस पृथ्वी पर किसी भी तरह के बिजनेस से जुड़ी किसी भी अन्य कंपनी का नहीं है।

अरामको का इतिहास

दुनिया भर में अपनी कमाई को लेकर चर्चित इस कंपनी की स्थापना अमरिकी तेल कंपनी ने की थी। अरामको यानी 'अरबी अमरीकन ऑइल कंपनी' का सऊदी अरब ने 1970 के दशक में राष्ट्रीयकरण कर दिया था। हालांकि यह कंपनी पारदर्शिता को लेकर विवादों में भी रही है।

दुनिया का सबसे बड़ा IPO- न्यूज एजेंसी के मुताबिक, इस आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर स्थानीय बाजार में लिस्ट होंगे, लेकिन हम विदेशी बाजार में लिस्टिंग के लिए भी तैयार हैं। पिछले एक हफ्ते पहले एक खबर में बताया गया था कि अरामको स्थानीय शेयर बाजार में पहली बार लिस्ट होगी और इसके बाद वह विदेशी बाजार में भी लिस्ट होगी। माना जा रहा है कि जापान में इसकी लिस्टिंग हो सकती है। अरामको की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि साल 2020 या 2021 में सरकारी कंपनी के 5 फीसदी शेयरों की लिस्टिंग होगी. यह दुनिया का सबसे बड़ा शेयर सेल होगा। यह आईपीओ सऊदी अरब के शासक क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान के सुधार कार्यक्रम का एक अहम हिस्सा है।

इससे पेट्रोलियम तेल पर सऊदी अर्थव्यवस्था की निर्भरता कम करने की योजना है। कंपनी अपने दो लाख करोड़ डॉलर मूल्य के आधार पर 100 अरब डॉलर तक इस आईपीओ से जुटाना चाहती है। निवेशक हालांकि कंपनी के इस मूल्य पर सवाल उठाते रहे हैं।

क्या होता है IPO- आईपीओ का मतलब इनीशियल पब्लिक ऑफर्स होता है। इसके लिए कंपनियां बाकायदा स्टॉक मार्केट में खुद को लिस्ट कराकर अपने स्टॉक्स इन्वेस्टर्स को बेचने का प्रस्ताव लाती हैं। स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के लिए कंपनी को अपने बारे में तमाम जानकारियां सार्वजनिक करनी होती हैं। यदि हम इसे आसान शब्दों में कहें तो कंपनी आईपीओ के माध्यम से अपने स्टॉक्स जारी करती है। दरअसल आईपीओ के जरिए कंपनियों के प्रमोटर पूंजी जुटाने के लिए अपनी कंपनी की कुछ हिस्सेदारी को बेचते हैं।

बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 150 अंक से अधिक की तेजी

मुंबई। बुनियादी संरचना, बैंकिंग और वाहन कंपनियों के शेयरों में तेजी आने से बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 150 अंक से अधिक मजबूत हो गया। बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स एक समय 150 अंक से अधिक की तेजी में चल रहा था। हालांकि बाद में इसमें कुछ गिरावट आयी और यह 89.72 अंक

यानी 0.24 प्रतिशत की तेजी के साथ 37,235.17 अंक पर चल रहा था। इसी तरह एनएसई का निफ्टी भी 21.55 अंक यानी 0.20 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,024.60 अंक पर चल रहा था। सोमवार को सेंसेक्स 163.68 अंक यानी 0.44 प्रतिशत की तेजी के साथ 37,145.45 अंक पर और निफ्टी 56.85 अंक यानी 0.52 प्रतिशत की बढ़त के साथ 11,003.05अंक पर बंद हुआ था। मंगलवार को मुहर्रम के कारण शेयर बाजार बंद रहे थे। सेंसेक्स की कंपनियों में येस बैंक, टाटा मोटर्स, वेदांता, टाटा स्टील, बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंडसइंड बैंक, मारुति सुजुकी, भारतीय स्टेट बैंक और एलएंडटी में छह प्रतिशत तक की तेजी रही। विशेषज्ञों के अनुसार, सकारात्मक वैश्विक संकेतों से बाजार की धारणा मजबूत हुई तथा सरकार के द्वारा अर्थव्यवस्था को सहारा देने के कदम उठाने से बाजार को उम्मीदें मिलीं। प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 188.08 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक 686.47 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे।

भारत के साथ FTA की समीक्षा को ASEAN राजी

नई दिल्ली। एजेंसी

दक्षिण एशियाई देशों के संगठन (ASEAN) ने द्विपक्षीय मुक्त व्यापार संधि (FTA) की समीक्षा करने की लंबे समय से चली आ रही भारत की मांग मान ली है। इससे भारत की यह चिंता दूर हो सकेगी कि उसे इस संधि से लाभ नहीं हो रहा है और 10 सदस्यों वाले एसोसिएशन के साथ उसका व्यापार घाटा बढ़ गया है। आसियान के सदस्य देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा वित्त वर्ष 2018 के 12 अरब डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2019 में 22 अरब डॉलर हो गया था। संयुक्त बयान के मुताबिक मंगलवार को दोनों पक्ष इऊँ को ज्यादा यूजर फ्रेंडली, आसान और कारोबार को बढ़ावा देनेवाली संधि बनाने को राजी हुए।

मंगलवार को बैंकाक में 16वें आसियान इकनॉमिक मिनिस्टर्स (AEM)-इंडिया मीटिंग में आसियान के सदस्य देशों के वित्त मंत्रियों और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के बीच करार हुआ। वस्तुओं के मामले में 2010 में लागू होने के बाद FTA की पहली समीक्षा

अब होगी। इऊँ में इंडिया के ज्यादा इंटरेस्ट वाले सर्विसेज कंपोनेंट पर डील पिछले साल साइन हुई थी और इसके इनवेस्टमेंट चैप्टर का अनुमोदन अभी नहीं हो पाया है। दोनों पक्षों ने समीक्षा के लिए संयुक्त समिति का गठन करने का भी फैसला किया। गोयल ने अधिकारियों को समीक्षा के ब्योरे पर काम करने और अगली मिनिस्ट्रियल मीटिंग में इस पर अपडेट देने का जिम्मा दिया है। भारत सरकार का मानना है कि इऊँ से उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर नेगेटिव असर हुआ है जबकि वह रोजगार सृजन के लिए मेक इन इंडिया अभियान के जरिए इसको बढ़ावा देने में जुटी है। वित्त मंत्रालय ने देश की अर्थव्यवस्था पर ऐसे करारों के असर का जायजा लेने के लिए इसके इऊँ फ्रेमवर्क की समीक्षा शुरू कर दी है। भारत सरकार ने आसियान की तिकड़ी के वाणिज्य मंत्रियों से कहा था कि आसियान के सदस्य देशों की तरफ से सर्विसेज के मामले में समुचित ऑफर करने के वादे पर अमल नहीं हुआ है।

भारत का कहना है कि ओरिजन नॉर्म्स का पालन नहीं होने और नियमों के ऐसे उल्लंघन की जांच और इनसे निपटने में पूरा सहयोग नहीं मिलने से इंडिया में माल का आयात तेजी से बढ़ा है। इसके उलट इंडिया- आसियान एफटीए के तहत प्रेफरेंशियल टैरिफ का इस्तेमाल भारत की तरफ से 30इ से भी कम हो रहा है, जिसकी वजह स्टैंडर्ड्स, रेगुलेटरी उपाय और आसियान रीजन में मौजूद दूसरे नॉन टैरिफ बैरियर हैं। इन देशों में भारत के बड़े एक्सपोर्ट प्रॉडक्ट्स में शिप, बोट, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल और मीट शामिल हैं। वह आसियान से टेलीकॉम इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, मिनरल फ्यूल, मिनरल ऑयल आदि मंगाता है।

स्वदेशी जागरण मंच के ऑल इंडियन को-कन्वेनर अश्विनी महाजन कहते हैं, 'FTA में कोई रिव्यू या एग्जिट क्लॉज नहीं था। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। आज हुए करार से यह दुखद स्थिति सुधर गई।' उन्होंने कहा कि सर्वाधिक नुकसान वाली इंडस्ट्री में स्टील, ग्लास, टेलीकॉम रही है। समीक्षा से ज्यादा निष्पक्ष वाणिज्यिक करार करने से इन सेक्टर के रिवाइवल में मदद मिल सकती है।

सऊदी अरब के नए पेट्रोलियम मंत्री ने उत्पादन कटौती का अनुमोदन किया

अबू धाबी। एजेंसी

सऊदी अरब के नए ऊर्जा मंत्री शहजादा अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की योजना का अनुमोदन कर दिया है। उन्होंने सोमवार को कहा कि इससे सभी तेल निर्यातक देशों को फायदा होगा। उनका यह बयान इस बात का संकेत है कि वह कीमतों में गिरावट तथा बाजार में अत्यधिक आपूर्ति को कम करने के लिए आगे और उत्पादन कटौती को समर्थन दे सकते हैं। अब्दुलअजीज बिन सलमान को उनके पिता शाह सलमान ने रविवार को मंत्री नियुक्त किया है। नियुक्ति के बाद यह उनका पहला बयान आया है। अब्दुलअजीज के इस बयान से स्पष्ट है कि सऊदी अरब के रुख में कोई विशेष बदलाव नहीं आया है। सऊदी अरब ओपेक का अगुवा देश है और इस गठजोड़ में एक तिहाई कच्चे तेल का योगदान उसके द्वारा किया जाता है। अब्दुलअजीज ने कहा कि हमारी नीति का स्तंभ पहले से तय है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। शहजादा अब्दुलअजीज विश्व ऊर्जा कांग्रेस में भाग लेने के लिए अबू धाबी में थे।

आर्थिक सुस्ती को दूर करने के लिए सरकार उठा सकती है ये कदम

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

आर्थिक क्षेत्र के विशेषज्ञ देश में मौजूदा आर्थिक सुस्ती के लिए मांग की कमजोरी को एक बड़ा कारण मानते हैं। इसे दूर करने के लिए कुछ जानकार घरेलू उपभोग बढ़ाने के उपायों पर जोर दे रहे हैं तो कुछ सरकारी निवेश में तेजी देखना चाहते हैं। कुछ अर्थशास्त्री ग्रामीण मांग बढ़ाने और वित्तीय प्रोत्साहन देने का सुझाव दे रहे हैं जबकि कुछ का कहना है कि भारत में वास्तविक ब्याज दर लंबे समय तक ऊंची होने से उपभोग और निवेश की मांग प्रभावित हुई है। आर्थिक सुस्ती गहराने के मूल में हालांकि, सभी का इशारा मांग की कमी होने की तरफ ही रहा है लेकिन मांग पैदा करने और अर्थव्यवस्था में गतिविधियां बढ़ाने के बारे में उनके सुझाव अलग अलग रहे हैं।

गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (उअ्ड) की वृद्धि दर छह साल के निम्न स्तर, पांच प्रतिशत पर पहुंच गई। रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा मौद्रिक समीक्षा में इस वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि का अनुमान सात प्रतिशत से घटाकर 6.9 प्रतिशत कर दिया। कुछ वैश्विक एजेंसियों ने इसके 6.5 प्रतिशत या उससे भी कम रहने का अनुमान जताया है। नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनैंस ऐंड पॉलिसी के प्रफेसर एनआर भानुमूर्ति कहते हैं, 'इस समय सरकार को सड़क, रेलवे, बिजली, ग्रामीण एवं शहरी आवास क्षेत्र की तमाम बड़ी परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना होगा ताकि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आए।'

'काफी पहले शुरू हुई थी आर्थिक मंदी'

भानुमूर्ति ने कहा, 'आर्थिक सुस्ती तो काफी पहले शुरू हो गई थी हालांकि, सरकार इसे अब महसूस कर रही है। इसकी वजह चक्रीय और स्ट्रक्चरल दोनों तरह की हैं।' उन्होंने कहा, 'आपको वित्तीय प्रोत्साहन देने होंगे, मौद्रिक उपाय का फिलहाल असर नहीं होगा। सरकार के वित्तीय प्रोत्साहनों का स्वरूप 2008- 09 की तरह नहीं होना चाहिए। सीधे उपभोक्ता खपत बढ़ाने वाले उपाय यदि होंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ सकती है इसलिए इससे बचना होगा। पूर्ववर्ती योजना आयोग में

शहरों में गरीबी की वजह से घटी मांग!

प्रधान आर्थिक सलाहकार रहे प्रणव सेन इस मामले में सीधे मांग की कमी को आर्थिक सुस्ती की वजह बताते हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में मांग कमजोर बनी हुई है। शहरी गरीब लोगों की आमदनी कम है। इससे जनसंख्या के एक बड़े तबके की मांग कमजोर बनी हुई है। उनका स्पष्ट मानना है कि अर्थव्यवस्था में आपूर्ति की कोई तंगी नहीं है बल्कि मांग की कमी बनी हुई है। उनका सुझाव है कि किसानों को सालाना 6,000 रुपये देने की पीएम किसान योजना पर तेजी से अमल होना चाहिए। ग्रामीण स्तरीय परियोजनाओं जैसे कि ग्रामीण सड़क योजना, लघु सिंचाई योजना, सस्ती आवास योजना पर काम तेज होना चाहिये। इनमें स्थानीय ठेकेदारों और स्थानीय कामगारों को काम दिया जाना चाहिए।

वहीं सेंटर फॉर ग्लोबल डिवेलपमेंट रिसर्च (सीजीडीआर) के निदेशक डॉ. कन्हैया सिंह ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः आपूर्ति प्रेरित है। देश में मानसून अच्छा रहता है तो बाजार में गर्मी आती है। इस तरह उद्योग धंधे मानसून की चाल पर निर्भर करते हैं। उन्होंने आर्थिक सुस्ती के स्वरूप पर एक अलग नजरिया पेश करते हुए कहा कि अप्रैल-जून 2019 की पहली तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि कम रही है लेकिन बिजली क्षेत्र की वृद्धि 8.62 प्रतिशत पर अच्छी रही है। विनिर्माण क्षेत्र अच्छा नहीं कर रहा है लेकिन अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत ठीक प्रदर्शन कर रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। बिजली क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा है तो इसकी खपत हुई उत्पादन भी हुआ लेकिन बिक्री नहीं हुई। यह पिछले साल के ऊंचे स्तर का भी असर हो सकता है।

'घरेलू बचत को देना होगा बढ़ावा'

भानुमूर्ति कहते हैं कि विदेशी जोखिम को कम करने के लिए घरेलू क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। घरेलू बचत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अवसंरचना बॉन्ड, कर मुक्त सुविधा वाले बॉन्ड जारी किए जा सकते हैं। प्रणव सेन का कहना है कि समस्या मांग की है जबकि सरकार के उपाय आपूर्ति बढ़ाने की तरफ अधिक हैं। बैंकों में नकदी उपलब्ध है लेकिन मांग नहीं है। कन्हैया सिंह कहते हैं कि भारत जैसे देश में मुद्रास्फीति को लक्षित दायरे में बांधना ठीक नहीं है। पिछले डेढ़ दो साल में मुद्रास्फीति कम रहने के बावजूद रिजर्व बैंक की रीपो दर ऊंची रखी गई। इसमें कमी नहीं की गई परिणामस्वरूप वास्तविक ब्याज दर ऊंची बनी रही। इसका निवेश पर असर पड़ता है। सिंह का मामना है कि 2019-20 की जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत के आसपास रहेगी। प्रणव सेन ने कहा वृद्धि 5.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी लेकिन भानुमूर्ति का मानना है कि यह 6 से 6.5 प्रतिशत के दायरे में रह सकती है।

Reliance
POLYMERS
Indore Depo :
131-132, Industrial Area,
Sector-D, Sanwer Road, Indore
Gwalior Depo :
C/o Bhagwati Cools Pvt.Ltd.
37-B, Maharajpura Industrial
Area, Gwalior
Raipur Depo :
C/o, Sun & Sun Cold Storage Pvt.Ltd.
Godown No.2, Industrial Area,
Bilaspur Road, Bhanpuri, Raipur

distribution redefined
AVJ POLYMER INDIA LLP
DEALER : RELIANCE INDUSTRIES LTD. FOR MP & CG
133, Industrial Area, Sector-D,
Sanwer Road, Indore (M.P.)
Ph: +91 731 2973343
Email : avjpolymer@gmail.com Website : www.avjpolymer.com
Vikas Bangard Mob- 9179161616
Vishal Soni Mob- 9826700343
Ashish Jain Mob- 9425044944
Rakesh Biyani Mob- 9109195565

विचार

आर्थिक सुस्ती के दौर में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध का फैसला सही नहीं है

प्लास्टिक की जगह प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जंग छेड़ने की ज़रूरत

इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब एक बार इस्तेमाल होने वाले (सिंगल-यूज) प्लास्टिक को निशाने पर लिया है। उनका ये नया युद्ध 2 अक्टूबर को आरंभ होगा जब वे प्लास्टिक की थैलियों, कप-प्लेटों, छोटे बोतलों, स्ट्रॉ और कई तरह के सैशे (पाउच) पर प्रतिबंधों का ऐलान करेंगे। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या सरकार में किसी ने सिंगल-यूज प्लास्टिक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के आर्थिक और पर्यावरणीय नफा-नुकसान का अध्ययन किया भी है। एक अनाम अधिकारी ने बताया है कि 'प्रतिबंध व्यापक होगा जिसके दायरे में ऐसी चीज़ों के निर्माण, उपयोग और आयात को शामिल किया जाएगा।

यह अभियान मोदी के कट्टर समर्थकों के साथ-साथ उनके वामपंथी विचारधारा वाले विरोधियों तथा राजनीतिक और वैचारिक मतों से परे, अधिकांश आम लोगों में भी लोकप्रिय साबित होगा। चूंकि सबको पता है कि प्लास्टिक की थैलियां पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए उन पर रोक का भला कौन विरोध करेगा?

प्लास्टिक की थैलियां और उनके विकल्प

प्लास्टिक की थैलियां और सिंगल-यूज प्लास्टिक के अन्य सामान पर्यावरण को दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। पहला नुकसान तो सबके सामने है- जैव-विघटनीय नहीं होने के कारण सड़कों पर तथा लैंडफिलों, नदियों, झीलों और समुद्रों में इनका जमा होते जाना और अंततः खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाना। इनसे जुड़ी समस्याएं विश्वव्यापी हैं, पर भारत के शहरों और गांवों में कचरा निस्तारण सुविधाओं के अभाव के कारण इनका प्रकोप ज़्यादा गंभीर है। दूसरा नुकसान अप्रत्यक्ष है, जो कि इन वस्तुओं के पर्यावरणीय फुटप्रिंट से संबद्ध है. यानि इनके उत्पादन, परिवहन और इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाला नुकसान,

प्लास्टिक की थैलियों से जुड़ा एक विरोधाभास ये है कि इनका सकल पर्यावरणीय फुटप्रिंट वास्तव में इसके विकल्पों के तुलना में बहुत छोटा है। डेनमार्क सरकार के 2018 के एक अध्ययन के अनुसार प्लास्टिक की एक थैली के समतुल्य पर्यावरणीय प्रभाव प्राप्त करने के लिए आपको कागज की एक थैली का 43 बार इस्तेमाल करना होगा।

जब कुछ साल पहले बेंगलुरु में प्लास्टिक की थैलियों पर रोक लगाई गई, तो किराना दुकान वाले 10 रुपये या उससे अधिक कीमत की सूती कपड़े की थैली बेचने लगे, पर प्लास्टिक की थैली के समतुल्य पर्यावरणीय प्रभाव हासिल करने के लिए कपड़े की एक थैली का 7,100 बार इस्तेमाल किया जाना होगा और यदि आप अत्यंत जागरूक हैं और ऑर्गेनिक सूती का बैग इस्तेमाल करते हैं तो आपको प्लास्टिक की 'बुरी' थैली के पर्यावरणीय फुटप्रिंट की बराबरी के लिए उसका 20,000 बार इस्तेमाल करना होगा।

भारत में वैसे तो थैलियों को बारंबार इस्तेमाल करने की पुरानी परंपरा है, पर कोई भी व्यक्ति एक पेपर बैग को 45 बार या कॉटन बैग को 7,000 बार इस्तेमाल कर सकता है। इसका सीधा मतलब यही हुआ कि प्लास्टिक की थैलियों की जगह कागज या कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल शुरू कर हम वास्तव में पर्यावरण का अधिक नुकसान करेंगे और अंततः जलवायु परिवर्तन में योगदान करेंगे। आप बस इन वैकल्पिक थैलियों के लिए कटने वाले पेड़ों तथा उनकी निर्माण प्रक्रिया में इस्तेमाल पानी-बिजली की मात्रा पर गौर करना होगा।

प्रतिबंध की असल कीमत

यदि सिंगल-यूज प्लास्टिक पर रोक की भारत की योजना सफल रही तो निश्चय ही हम प्लास्टिक प्रदूषण में कमी ला सकेंगे, पर इसी के साथ हम पर्यावरण को होने वाले सकल नुकसान में इजाफ़ा भी करेंगे। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार की योजना प्लास्टिक की थैलियों से बहुत आगे तक चोट करती है, क्योंकि इसमें प्लास्टिक कप-प्लेट और पैकेजिंग में काम आने वाले प्लास्टिक के सामान भी शामिल हैं. पर ये संभव नहीं दिखता कि प्लास्टिक का कोई विकल्प पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह साबित होगा। इस विषय में आंकड़ों पर किसी ने गौर किया होगा। पर्यावरण का विषय होने के कारण ज़िम्मेदारी भरा कदम तो ये होता कि प्लास्टिक पर राष्ट्रव्यापी रोक की घोषणा से पूर्व भारत में अरबों की संख्या में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की चीज़ों को हटाने के मुद्दे पर एक विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाता।

प्लास्टिक पर रोक के आर्थिक फायदे मुख्यतः पैकेजिंग इंडस्ट्री में नए निवेश और नवाचार के रूप में सामने आएंगे, हालांकि ये फायदे मध्यम अवधि में ही मिल पाएंगे। प्रतिबंध के कारण प्लास्टिक इंडस्ट्री में वर्तमान निवेश, मशीनरी, व्यवसाय, नौकरियों आदि को भारी नुकसान पहुंचेगा। बर्बादी का वास्तविक स्तर प्रतिबंध के प्रावधानों पर निर्भर करेगा। प्रतिबंधित मशीनरी कंपनियों पर बोझ बन जाएंगी और उन्हें नई मशीनें लगाने का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ेगा. बड़ी कंपनियां तो शायद अतिरिक्त पूंजी निवेश के भार को झेल जाएं, पर छोटे और मंझोले स्तर के उद्यम खुद को भारी परेशानी में घिरा

पाएंगे. और ये सब ऐसे समय होने वाला है जब भारतीय अर्थव्यवस्था पहले ही नकदी के संकट से जूझ रही है।

प्लास्टिक बैन का दुष्प्रभाव गरीबों को कहीं अधिक झेलना पड़ेगा. दूध, बिस्किट, शैंपू आदि की पैकेजिंग हो या फिर प्लास्टिक की थैलियां, इनकी वजह से कई आवश्यक चीज़ें गरीबों के लिए आसानी से और सस्ते में उपलब्ध हो पाती हैं. इसलिए पैकेजिंग की लागत में बढ़ोतरी का सीधा असर गरीबों के पास खर्च के लिए उपलब्ध पैसे पर पड़ेगा।

सुपरमार्केट वालों के लिए ग्राहकों से प्लास्टिक की थैली के बदले 10 रुपये वसूल करना भले ही आसान हो, गलियों में फल-सब्ज़ी बेचने वाले ऐसा नहीं कर सकते। अपनी थैलियां साथ लाने की ग्राहकों की असुविधा का खामियाज़ा भी छोटे दुकानदारों को ही उठाना पड़ेगा। जब पश्चिमी देशों के चलन को हम आमदनी के भारतीय स्तर पर थोपेंगे, तो इस कथित सदाचार का आर्थिक बोझ गरीबों को ही उठाना पड़ेगा।

आर्थिक सुस्ती के दौर में क्या ये ज़रूरी है?

मोदी सरकार के नीति नियंताओं को इस बात को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हमारी अर्थव्यवस्था आर्थिक सुस्ती के दौर से गुजर रही है। यदि सिंगल-यूज प्लास्टिक से छुटकारा पाना सही है भी तो क्या इसके लिए ये सही समय है? सिंगल-यूज प्लास्टिक पर रोक नहीं लगाने का विकल्प क्या है? विभिन्न अध्ययनों के अनुसार इसका जवाब पुनर्प्रयोग और निस्तारण में है। एक आदर्श शॉपिंग बैग वो हो सकता है जो कपड़े से और घर में मौजूद साधनों से ही बनाया जाए, और फिर फटने तक जिसका इस्तेमाल किया जाए। इसलिए सरकार की नीति पुनर्प्रयोग वाले थैलों की डिज़ाइनिंग और उत्पादन के लिए उद्योग को प्रोत्साहित करने और पुनर्प्रयोग के महत्व पर जनता को जागरूक करने पर केंद्रित होनी चाहिए। इस पर धीरे-धीरे अमल हो, प्रोत्साहन का तरीका अपनाया जाए, ना कि सख्त प्रतिबंध लागू करे। एक तरह से, प्लास्टिक पर प्रतिबंध को सरकार की परोक्ष स्वीकारोक्ति ही मानी जाएगी कि वह कचरा निस्तारण का एक सक्षम तंत्र बनाने में नाकाम रही है. इसलिए शुरुआत यहीं से हो – नगरपालिकाओं को कचरा प्रबंधन में निवेश करने के लिए कहा जाना चाहिए। प्लास्टिक के खिलाफ जंग की जगह प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जंग छेड़ने की ज़रूरत है।

नए मोटर वीइकल ऐक्ट के बाद 6 गुना बढ़ा इंश्योरेंस रिन्यूअल

चैन्नई। एजेंसी

नए मोटर वीइकल ऐक्ट 2019 के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग भारी जुर्माना भर रहे हैं। इस ऐक्ट में संशोधन के बाद पिछले कुछ दिनों में इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल (नवीकरण) के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसमें 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। कई मामलों में यह वृद्धि छह गुना तक है।

सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख (अंडरराइटिंग ऐंड क्लेम्स) संजय दत्ता ने बताया, 'पुराने वाहनों के इंश्योरेंस रिन्यूअल से संबंधित पूछताछ में औसतन 3 से 4 गुना वृद्धि हुई है। कंज्यूमर्स निश्चित रूप से मोटर वीइकल ऐक्ट में संशोधन का संज्ञान ले रहे हैं और उसका पालन करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों डिस्ट्रिब्यूशन प्लैटफॉर्म पर

ट्रैफिक को देखना है।'

क्या कहते है मोटर इंश्योरेंस एक्सपर्ट

पॉलिसीबाजारडॉटकॉम के अनुसार दो पहिया वाहनों से जुड़ी पॉलिसी का रिन्यूअल पिछले एक हफ्ते से प्रतिदिन 10 हजार से बढ़कर 60 हजार पर पहुंच गया है। कार के बीमा रिन्यूअल में 70 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह प्रतिदिन के 3,500 से बढ़कर 6 हजार पर पहुंच गया है। पॉलिसी बाजार डॉट कॉम के मोटर इंश्योरेंस के बिजनस हेड सज्जा प्रवीण चौधरी ने बताया, 'इस दर पर हम अगले हफ्ते के आखिर तक 1 लाख पॉलिसी के रिन्यूअल की उम्मीद कर रहे हैं।'

चौधरी ने कहा, 'इससे पहले हमारी वेबसाइट पर अपनी पॉलिसी का रिन्यूअल कराने के लिए 100 विजिटर्स में से करीब 60 फीसदी दोपहिया वाहन वाले थे जबकि कारों के लिए यह संख्या 30 फीसदी थी। हालांकि पिछले 4 दिन से 87 प्रतिशत बाइक मालिकों और 52 फीसदी कार मालिकों ने इसके लिए ऐप्लिकेशन दिया।'

क्या है मोटर इंश्योरेंस से जुड़ा नियम

नए नियम के मुताबिक बिना इंश्योरेंस वाले वाहनों के पहली बार पकड़े जाने पर 2000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान है। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल हो सकती है। इससे पहले इस अपराध के लिए 1 हजार रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल का प्रावधान था। इंडस्ट्री के मुताबिक मोटर इंश्योरेंस अभी दो पहिया वाहनों के लिए 35 से 40 फीसदी, पैसेंजर कार के लिए 65 से 70 फीसदी और कमर्शल वाहनों के लिए 85 फीसदी है।

तेल कंपनियों ने विमान ईंधन पर करों को तर्कसंगत बनाने की राह में आने वाली बाधाओं को उजागर किया

नयी दिल्ली। एजेंसी

तेल विपणन कंपनी ने बिक्री कर जैसे मुद्दों का हवाला देते हुए कहा कि ये ममले हवाई अड्डों पर उलब्ध कराए जाने वाले विमान ईंधन पर अतिरिक्त शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की नागर विमानन मंत्रालय की योजना की राह में बाधक बने हुए हैं। एयरलाइन कंपनियों को देश के हवाई अड्डों पर विमान ईंधन (एटीएफ) भरवाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होता है। अधिकारियों ने यह बात कही। वर्तमान में , एयरलाइन कंपनियों कुछ सेवाओं के लिए कर का भुगतान कर रही हैं। उन्हें किसी भी हवाई अड्डे पर एटीएफ भरवाने पर ' थ्रूपुट शुल्क ', ' इंटुप्लेन शुल्क ' और ' ईंधन अवसंरचना ' शुल्क देना पड़ता है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि इन शुल्कों पर कई बार लगाया जाता है क्योंकि इनका बिल कई बार बनाया जाता है। एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय ने एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डा परिचालकों के बीच सीधा बिलिंग तंत्र विकसित करने के लिए एक समिति गठित की है ताकि बार - बार लगने वाले करों को हटाया जा सके।

इस समिति में एयरलाइंस कंपनियों , हवाई अड्डा परिचालक , तेल विपणन कंपनियों और अन्य सेवा प्रदाता इकाइयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। सरकार के अनुमान के मुताबिक , यदि सीधे बिल कटने की व्यवस्था को अमल में लाया जाता है तो एयरलाइंस कंपनियों को सालाना करीब 400 करोड़ रुपये बचेगा। भारत में , किसी भी एयरलाइन के कुल खर्च का 40 प्रतिशत हिस्सा विमान ईंधन में जाता है। इसलिए विमान ईंधन पर किसी भी प्रकार के कर का कंपनियों पर गहरा असर पड़ता है। अधिकारी ने कहा कि तेल विपणन कंपनियों ने हमें बताया है कि राज्य - स्तर पर बिक्री कर व्यवस्था के साथ उत्पाद कर व्यवस्था में कुछ प्रावधान हैं , जो सीधी बिलिंग प्रक्रिया को रोक सकता है।

अधिकारी ने कहा कि तेल कंपनियों राज्य सरकारें बिल पर लगने करों से होने वाली आय को खोना नहीं चाहेंगी। उन्होंने कहा कि समिति के जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। मामले को समझाते हुए पहले अधिकारी ने कहा थ्रूपुट शुल्क के लिए बिल का उदाहरण लेते हैं। यह शुल्क तेल कंपनियों पर हवाई अड्डा परिचालक लगाते हैं। तेल कंपनियां इस शुल्क को एयरलाइंस के बिल में जोड़ती है। हालांकि , जटिल बिलिंग प्रक्रिया के कारण थ्रूपुट शुल्क पर जीएसटी और उत्पाद शुल्क और वैट जैसे करों को जोड़ा जाता है। ' अधिकारी ने कहा कि यदि दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचाल सिर्फ 100 रुपये का थ्रूपुट शुल्क लगाती है तो एयरलाइन कंपनी को ' कर पर कर ' के चलते 164 रुपये का भुगतान करना होता है।

केरल देश का पहला महिला वैश्विक व्यापार केंद्र खोलेगा

तिरुवनंतपुरम। एजेंसी

महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केरल ने कहा कि वह देश का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र (आईडब्ल्यूटीसी) स्थापित करेगी। यह कोझीकोड में होगा। सरकार का कहना है कि संयुक्तराष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को पाने और लैंगिक समानता के लिए इसकी स्थापना की जाएगी। यह सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की 'जेंडर पार्क' परियोजना का अहम हिस्सा है। इस व्यापार केंद्र का मकसद महिलाओं को घर से दूर उनकी उद्यमी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना है। वह यहां अपने कारोबार का विस्तार कर सकेंगी और अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर पहुंचा सकेंगी। आईडब्ल्यूटीसी के पहले चरण को 'जेंडर पार्क' के 'विजन 2020' लक्ष्य के तहत पूरा किया जाएगा। इसके 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है। केरल के स्वास्थ्य एवं सामाजिक न्याय मंत्री के. के. शैलजा ने कहा कि जेंडर पार्क का आईडब्ल्यूटीसी परियोजना की घोषणा करना महत्वपूर्ण है, वह भी ऐसे समय में जब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं उद्यम को अपना रही हैं और स्वरोजगार के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश रही हैं।

ओएनजीसी तेल के कुओं की खुदाई के लिये असम में करेगी 13 हजार करोड़ रुपये का निवेश

गुवाहाटी। एजेंसी

ओएनजीसी ने असम में तेल एवं गैस के 220 से अधिक कुओं की खुदाई करने के लिये अगले पांच साल में 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करने की बुधवार को घोषणा की। कंपनी ने कहा कि उसने राज्य में खोज तथा उत्पादन की गतिविधियों को विस्तार देने के लिये असम सरकार के साथ एक समझौता किया है। कंपनी ने कहा कि तेल एवं गैस के 220 से अधिक कुओं की खुदाई के लिये यह निवेश किया जा रहा है। कंपनी ने कहा, "ओएनजीसी 2022 तक तेल आयात 10 प्रतिशत कम करने के प्रधानमंत्री के आह्वान तथा पूर्वोत्तर हाइड्रोकार्बन विजन 2030 को ध्यान में रखते हुए अपनी गतिविधियां बढ़ाने पर जोर दे रही है।

पेयजल के लिए वैकल्पिक पैकेजिंग की तलाश करने को कहा खाद्य मंत्रालय ने

नयी दिल्ली। एजेंसी

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बोतलबंद पानी बेचने वाली पेप्सी और कोका कोला जैसी कंपनियों को तीन दिनों में पैकेजिंग की वैकल्पिक सामग्री का सुझाव देने को कहा है। पासवान स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्लास्टिक के प्रभाव के कारण पैकेजिंग में इसके उपयोग पर पाबंदी के पक्षधर हैं। उन्होंने सोमवार को बताया कि मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है। इस समिति को एक ही बार में या चरणबद्ध तरीके से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर गौर करने के लिए कहा गया है। पासवान ने सोमवार को बोतलबंद पानी उद्योग और विभिन्न सरकारी विभागों के साथ बैठक की जिसमें पीने के पानी को पैकबंद करने के लिए एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की बोतलों का उपयुक्त विकल्प खोजने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में, उपभोक्ता मामलों के सचिव ए के श्रीवास्तव तथा पर्यावरण और रासायनिक मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भारतीय मानक ब्यूरो(बीआईएस), खाद्य नियामक एफएसएसएआई, आईआरसीटीसी के वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित थे। मंत्री ने कहा, मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में प्लास्टिक की बड़ी भूमिका है। हमने गायों के पेट में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक पाये जाने की खबरें सुनी है। पासवान ने कहा कि 'रीसाइक्लिंग' (पुनर्चक्रीकरण) भी कोई स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए एक विकल्प खोजने की जरूरत है, जो समान रूप से सस्ती और विश्वसनीय हो। उन्होंने कहा कि शुद्ध कागज की बोतल भी कोई विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि उससे बनने वाले पैक में कुछ प्लास्टिक मिला होता है। मंत्री ने कहा हमें इस बैठक के दौरान पैकबंद पेयजल का कोई ठोस विकल्प नहीं मिला है। इसलिए, मैंने सभी निर्माताओं से अपने सुझाव 11 सितंबर तक भेजने को कहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सिफारिशों को प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) और अंतर-मंत्रालयी समिति को भेजा जायेगा। पासवान ने कहा कि इस बारे में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने कहा, मैं अपील करना चाहता हूं कि प्लास्टिक की वजह से प्रदूषण और विभिन्न बीमारियां फैलती हैं। पुनर्चक्रण एक विकल्प है लेकिन यह एक स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान यह है कि प्लास्टिक को हटाया जाना चाहिए और इस पर प्रतिबंध होना चाहिए। मंत्री से जब इस प्रतिबंध के कारण उद्योग और अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभावों के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इस प्रतिबंध से रोजगार प्रभावित नहीं होगा क्योंकि वैकल्पिक सामग्री के कारण रोजगार पैदा होगा। मंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय, जो 'रेल नीर' ब्रांड के तहत पैकबंद पेयजल बनाता और बेचता है, भी इस मुद्दे पर विचार कर रहा है। 'ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ नेचुरल मिनरल वाटर इंडस्ट्री' के सचिव बेहराम मेहता ने कहा कि पैकेज्ड पानी उद्योग, पीईटी (पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट) का इस्तेमाल करती है, जिसका 100 फीसदी पुनचक्रीकरण किया जा सकता है और इसका वैश्विक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने कहा कि पैकबंद पानी उद्योग ने 92 प्रतिशत रीसाइक्लिंग का स्तर हासिल किया है और जल्द ही इस मामले में 100 प्रतिशत हासिल कर लेगा। मेहता, जो एबीए नेचुरल मिनरल के प्रबंध निदेशक हैं, ने कहा कि बोतलबंद पानी उद्योग का आकार 30,000 करोड़ रुपये का है। पूरे प्लास्टिक उद्योग 7.5 लाख करोड़ रुपये का है और इसमें सात करोड़ लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। मेहता ने जोर देकर कहा कि कागज, कांच और स्टील न तो एक किफायती विकल्प हैं और न ही पर्यावरण के अनुकूल हैं।

सत्कार्य करने की शक्ति देते हैं परमपुरुष

जीवन का वास्तविक लक्ष्य आध्यात्मिक हुए बिना नहीं पाया जा सकता। और इसके लिए भक्ति चाहिए। भक्ति के लिए कर्म करना पड़ेगा। अगर आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा आपकी मदद जरूर करेंगे।

अध्यात्म

श्री श्री आनन्दमूर्ति

मनुष्य का लक्ष्य है एक स्थायी सत्ता, जिसके नहीं होने से कर्म स्थायी नहीं हो सकता है। कोई मनुष्य यदि कुछ स्थायी करना चाहता है, कोई नई चीज बनाना चाहता है और समाज का कल्याण करना चाहता है तथा मनुष्य के रूप में जीवन में जो चाहा है, उसे अगर प्रतिष्ठित करना चाहता है, तब उसे आध्यात्मिक जीवन में प्रतिष्ठित होना ही होगा। भक्ति और प्रेरणा को छोड़ कर मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता।

अभी भी देखा जाता है कि साधना से, कर्म से, मनुष्य के भीतर आध्यात्मिक प्रेरणा और भक्ति जग जाती है। अनेक लोग सम्भवतः सोच सकते हैंकि बिना ज्ञान, कर्म साधना किए उनकी भक्ति कैसे जगी? तो इसके उत्तर में मैं कहूंगा- यह उनके पूर्व-कृत कर्म की प्रतिक्रिया है। कभी अर्थात पूर्वजन्म में उसने जो ज्ञान और कर्म की साधना की थी, उसके फल के रूप में इस जीवन में ज्ञान और कर्मसाधना बिना किए ही उसे भक्ति मिली है। अनेक लोगों की यह धारणा है कि भक्ति के साथ ज्ञान और कर्म का कोई सम्पर्क नहीं है, किन्तु इस प्रकार सोचना बिल्कुल गलत है। भक्ति कभी भी ज्ञान वर्जित या कर्म वर्जित नहीं हो सकती।

भक्ति, ज्ञान और कर्म का समन्वय है- इसलिए भक्ति में ज्ञान और कर्म की पराकाष्ठा रहनी ही होगी। कोई यदि सोचे कि चौबीस घंटा दरवाजा बंद कर प्राणायाम करता रहेगा, तो इस स्थिति में वह अभीष्ट को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके भीतर जड़ता है, कर्म का अभाव है; और भक्ति तो ज्ञान और कर्म का समन्वय है। इसलिए कोई यदि चौबीस घंटा जप-तप ही किए जाए, तो वह इष्ट को नहीं पा सकता। वह कर्म का गुलाम हो जाएगा, उसका स्वभाव यंत्र के जैसा हो उठेगा। यंत्र भी खूब खटता है, खूब घूमता-फिरता है, किन्तु क्या इसीलिए उस यंत्र के द्वारा ज्ञान और भक्ति साधना सम्भव है? ज्ञान और कर्म ठीक गंगा-यमुना जैसे हैं, इन दोनों के मिल जाने से ही जीवन की सार्थकता उपलब्ध होती है। जिसके भीतर भक्ति जगी है, उसे उपयुक्त कार्य में रत होना ही होगा, काम उसे चुन लेना ही होगा। यदि वह स्वयं नहीं समझ सके कि उसे क्या कार्य करना है, वह दूसरे से परामर्श लेगा, किन्तु सब समय उसे कार्य करते जाना होगा। चूंकि उसमें जो भक्ति जगी है, उसके अन्दर आध्यात्मिक प्रेरणा जगी है, जिस कार्य में वह हाथ लगाएगा, उसमें वह सफलता पाएगा ही। कार्य में कूद जाने से, कार्य में उतर पड़ने से, देखोगे कि तुम सब कुछ कर सकते हो। कभी नहीं सोचो कि क्या मैं कर सकूंगा? कार्य में उतरो, उसे अवश्य, अवश्य ही कर सकोगे। जब समाज के कार्य में लग जाओगे, तब समाज तुम्हारी कभी अवहेलना नहीं कर सकता, समाज की अग्रगति के माध्यम से ही जीवन को परिपूर्णता मिलेगी।

जड़ जगत के संवेग या आकर्षण से मानस जगत् का संवेग या आकर्षण बहुत अधिक शक्तिशाली है। और आध्यात्मिक जगत का संवेग या आकर्षण और भी अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य यदि संदेह से सोचे कि क्या मैं कर सकूंगा, मेरे द्वारा क्या कार्य होगा- इस तरह यदि वह कार्य करना आरम्भ करे, तो उसके द्वारा कभी भी कार्य नहीं हो सकेगा। साहस के साथ अपने लक्ष्य पर ध्यान रख, आध्यात्मिक प्रेरणा के द्वारा सराबोर होकर यदि वह कार्य आरम्भ करे, तो सफलता उसे मिलेगी ही। कोई भी कार्य मनुष्य से बड़ा नहीं है। पृथ्वी पर, वास्तविक जगत में, व्यावहारिक जगत में, जो कुछ हम लोग पाते हैं, जो कुछ हमारी पकड़ में आता है- उनमें सबसे बड़ा और शक्तिशाली मनुष्य है। सभी कार्यों से मनुष्य बड़ा है। केवल कार्य की सिद्धि या असिद्धि के ऊपर निर्भर कर; पवित्रता या अपवित्रता की दीवार बना हम लोग मनुष्य के मान का निर्धारण करते हैं। मनुष्य के साथ कार्य का इतना ही सम्बंध है। मनुष्य जो कार्य करता है, वह यदि सिद्ध हो, पवित्र हो, बृहत् हो, तो हम लोग महान मान कर स्वीकार करते हैं। इसलिए किसी कार्य को करने के पहले विवेचक मन से जब सोच कर देखोगे कि कार्य सत् है, तो उसी मुहूर्त में कर्म समुद्र में कूद पड़ोगे। तुम्हारी जय होनी ही है।

साधारणतः मनुष्य जिस कार्य में हाथ लगाने लगता है, वह सिद्ध है या असिद्ध, पवित्र है या अपवित्र, यह विचार कर नहीं देखता है। सोचता है, कार्य वह कर सकेगा या नहीं! जब वह देखेगा कि वह कर्म कल्याणप्रद है, तभी उसे कूद पड़ना होगा; क्योंकि जिस सत् बुद्धि ने प्रेरणा दी है, उसके आधार हैं परमपुरुष। इसलिए उस कार्य को भलीभांति करने की शक्ति वे निश्चय ही देंगे।

प्रस्तुतिः दिव्यचेतनानन्द अवधूत

मुहर्रम (10 सितंबर) पर विशेष

शहादत का संदेश देता है मुहर्रम

विश्व ने अगणित दुखदायी व आत्मा को झकझोरने वाली घटनाएं और मातम करने वालों के आंसुओं के दरिया बहते देखे होंगे। मगर इतिहास के किसी भी दौर में मनुष्य ने इतने अधिक आंसू न बहाए होंगे और मातम न किया होगा, जितना कि करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर हुआ!

नबी के प्यारे हजरत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामी कैलेंडर के अनुसार तीन शाबान चार हिजरी (8 जनवरी, 626) सोमवार को हुआ था। हुसैन की मां रसूल-ए-मकबूल हजरत मुहम्मद की सबसे प्यारी बेटी हजरत फातिमा थीं। आपके पिता का नाम हजरत अली था। हजरत मुहम्मद ने ही आपका पालन-पोषण किया था। हदीसों से ज्ञात होता कि रसूलल्लाह हजरत मुहम्मद को अपने नवासे इमाम हुसैन से बड़ा स्नेह था। एक बार की बात है कि हजरत फातिमा के घर के आगे से हजरत मुहम्मद का गुजरना हुआ। इमाम हुसैन के रोने की आवाज आई। आप फौरन हजरत फातिमा के पास गये और कहा, 'बेटी, तू इस बच्चे को रुला कर मुझे दुख देती है।' इतना प्यार था हमारे रसूल को अपने नवासे से। इसी प्रकार एक बार की बात है कि हजरत मुहम्मद साहबा-ए-कराम के बीच में बैठे थे तो उन्होंने कहा, 'हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ऐ खुदा जो हुसैन को दोस्त रखता है, तू उसे दोस्त रख। जिसने मुझसे मुहब्बत की, उसने खुदा से मुहब्बत की।'

हजरत इमाम हुसैन अपने नाना व साहाबा-ए-कराम के संरक्षण में पले-बढ़े और इसी प्रकार के समाज में रहे। इसीलिए हजरत इमाम हुसैन के अंदर वही विशेषताएं आ गई थीं, जो उनके नाना में थीं। सच बोलना, निडर रहना, इंसाफ पसंदी, मनुष्यता, धैर्य, सच्चाई, सहनशक्ति आदि विशेषताएं हजरत इमाम हुसैन में थीं, जिसके कारण उन्होंने यजीद और उसके साथियों का अंतिम सांस तक मुकाबला किया। आने वाली नस्लों के लिए हुसैन और उनके परिवार का बलिदान परम बलिदान बन गया।

मुहर्रम में बलिदान की याद ताजा की जाती है। मास मुहर्रम की पहली से दसवीं तिथि (दसवीं को हुसैन शहीद हुए) तक नौ दिनों को अशरा-ए-मुहर्रम कहते हैं। दसवीं को आशूरा कहते हैं। तमाम विश्व के मुसलमान हुसैन की शहादत को याद करने के लिए जुलूस निकालते हैं। इसके अतिरिक्त मजलिसें भी की जाती हैं। हजरत इमाम हुसैन को याद करने के लिये स्वयं को कष्ट दिया जाता है। लोग बयान सुनते हैं और रोते हैं। मुहिब्बान-ए-हुसैन (हुसैन से प्यार करने वाले) अपना सर और सीना पीटते हैं।

इसके अतिरिक्त याद-ए-हुसैन में रंग-बिरंगे ताजिये भी निकाले जाते हैं, जिनको अस्र की नमाज के समय (जिस समय हुसैन को शहीद किया गया) अपने-अपने नगर की करबला के मैदान में दफना दिया जाता है।

करबला का सबक: करबला ने हमें सिखाया है कि जीवन चंद रोज का ही है और असल जीवन तो आखिरत (मृत्योपरान्त) में ही प्रारम्भ होता है। भगवान की बात को मानना परम धर्म है और सदा हक, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे शत्रु कितना ही मजबूत क्यों न हो। खुद में इतनी सहनशीलता लाओ कि शत्रु वार करते-करते थक जाए। अपने हक की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहो। जिल्लत के जीवन से इज्जत की मृत्यु अच्छी है।

फिरोज बख्त अहमद

पितृपक्ष (13-28 सितंबर) पर विशेष

पितरों को श्रद्धा का अर्पण

ब्रह्म पुराण के श्राद्ध प्रकाश में कहा गया है कि जो उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार, शास्त्रोचित विधि से पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता है, वह श्राद्ध है। मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य के तीन पूर्वज- पिता, पितामह एवं प्रतिपामह क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय इनको पूर्वजों का प्रतिनिधि माना गया है।

ऋग्वेद में पितृगण निम्न, मध्यम और उच्च, तीन श्रेणियों के बताए गए हैं। तैतरीय ब्राह्मण में उल्लेख है कि पितर लोग जिस लोक में निवास करते हैं, वह भू-लोक और अंतरिक्ष के बाद है। पितरों के लिए श्रद्धापूर्वक हम जो कुछ भी अर्पण करते हैं, उसे अग्नि देव उनके निकट पहुंचा देते हैं, तभी तो सूर्यास्त के बाद यह अनुष्ठान नहीं किया जाता। बौधायन धर्मसूत्र में वर्णन है कि जो पितृ कर्म करता है, उसे दीर्घायु, स्वर्ग, यश और समृद्धि प्राप्त होती है।

ऐसे तो भारत में कितने ही तीर्थों पर श्राद्ध, पिण्डदान किया जाता है, लेकिन उनमें गयाजी को सबसे उत्तम माना गया है। वशिष्ठ धर्मसूत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि कृषक जैसे अच्छी वर्षा से प्रसन्न होते हैं, वैसे ही गया में पिण्डदान से पितर प्रसन्न होते हैं। नारद पुराण के उत्तर भाग में वर्णन है- 'हे! सुभाग्ये महापापकर्त्ता पातकी भी, जो पितृ कर्म का अधिकार रखता हो, गया के दर्शन व वहां श्राद्ध करने से ब्रह्मलोक पा जाता है।'

विष्णु के जाग्रत तीर्थ गया में पूरे वर्ष भर पिण्डदान होता रहता है, लेकिन प्रत्येक वर्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक का काल, जिसे पितृपक्ष कहा जाता है, में गया में अनुष्ठान का विशेष महत्व है। इस अवधि में पितृगण 'गया श्राद्ध' के लिए आस लगाए रहते हैं। गया में किया गया श्राद्ध लोक व परलोक दोनों के लिए सुखकारी है।

डॉ. राकेश सिन्हा 'रवि'

कूर्म पुराण के श्राद्ध प्रकरण के अनुसार विभिन्न दिनों को किए गए श्राद्ध का पुण्य फल

सोमवार - सौभाग्य वृद्धि	गुरुवार - धन प्राप्ति
मंगलवार - संतति प्राप्ति	शुक्रवार - समृद्धि प्राप्ति
बुधवार - शत्रु नाश	शनिवार - आरोग्य सुख
	रविवार - यश प्राप्ति

तिथि के अनुसार श्राद्ध का पुण्य फल

प्रतिपदा - धन लाभ	प्राप्ति
द्वितीया - आरोग्य	दशमी - कामना पूर्ति
तृतीया - संतति प्राप्ति	एकादशी - वेद ज्ञान की प्राप्ति
चतुर्थी - शत्रु नाश	द्वादशी - सर्वत्र विजय
पंचमी - लक्ष्मी प्राप्ति	त्रयोदशी - दीर्घायु व ऐश्वर्य प्राप्ति
षष्ठी - पूज्यता प्राप्ति	चतुर्दशी - अपघात से हुए मृतकों की तृप्ति
सप्तमी - गणों का आधिपत्य प्राप्ति	अमावस्या - कामना पूर्ति व स्वर्ग की प्राप्ति
अष्टमी - उत्तम बुद्धि की प्राप्ति	
नवमी - उत्तम स्त्री की	

ऑडी इंडिया ने लांच की लिमिटेड-ऐडिशन ऑडी क्यू 7 ब्लैक ऐडिशन

मुंबई। जर्मन लक्जरी कार मैन्युफैक्चरर ऑडी ने अपनी फ्लैगशिप एसयूवी ऑडी क्यू7 का ब्लैक ऐडिशन लांच किया। लिमिटेड ऐडिशन, बेहद लोकप्रिय ऑडी क्यू7 ने फुल साइज़ लक्जरी क्लास में अपनी उत्कृष्टता को कायम रखा है और यह कई फीचरों व ऐक्सैसरीज़ से युक्त है जो इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना देते हैं। ऑडी क्यू7 ब्लैक ऐडिशन का ब्लैक स्टाइलिंग पैकेज हाई क्वालिटी ऐक्स्टीरियर को पूर्णता देता है जबकि वाहन की डायनमिक साइड लाइंस इसे ऐग्रैसिव अपियरेंस देती हैं।

ऑडी क्यू7 ब्लैक ऐडिशन की कीमत रु. 82,15,000 है और भारत में केवल 100 यूनिट बुकिंग के लिए उपलब्ध हैं। इस लांच के बारे में ऑडी इंडिया के प्रमुख श्री बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, ''लक्जरी एसयूवी सैगमेंट में ऑडी अग्रणी है और खास तौर पर ऑडी क्यू7 ने अपने लांच के वक्त से ही अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त को बरकरार रखा है। लक्जरी के शीर्ष पर हमारे उपभोक्ता अपना अलग व्यक्तित्व और विषिष्टता को दर्शना चाहते हैं, नई ऑडी क्यू 7 ब्लैक ऐडिशन हमारे उपभोक्ताओं को बिल्कुल वही प्रदान करेगी- बेहतरीन फीचर्स और इनोवेटिव ऐक्सैसरीज़, लिमिटेड ऐडिषन मॉडल में। हम ऑडी क्यू 7 ब्लैक ऐडिशन की सिर्फ 100 यूनिट बेच रहे हैं और हमें यकीन है कि ऑडी परिवार के सदस्य व लक्जरी के कद्रदान इस आकर्षक कार के मालिक बनने के मौके का लाभ उठाएंगे। त्योहारों के इस मौसम में ग्राहकों को उत्साहित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया 30 प्रतिशत डैप्रिसिएसन कारगर साबित होगा।''

विशेषता कायम रखने के लिए केवल 100 यूनिट पेश की जा रही हैं कीमत रु. 82,15,000 से शुरु होती है

ऑडी क्यू7 ब्लैक ऐडिषन को रेडिएटर ग्रिल फ्रेम, हॉरिज़ॉन्टल रेडिएटर ग्रिल स्ट्रट व लेटरल एयर इन्टेक स्ट्रट (टाइटेनियम ब्लैक ग्लॉस में) के साथ प्रस्तुत किया गया है। ऑडी क्यू7 की डायनमिक ऑफ-रोडिंग क्षमताओं को हाइलाइट करने के लिए डोर ट्रिम स्ट्रिप्स को टाइटन ब्लैक ग्लॉसी में क्वात्रो ऐम्बॉसिंग के संग पेष किया गया है। साइड विंडोज़ और रूफलाइन पर फ्रेम मोल्डिंग हाई ग्लॉस ब्लैक में है तथा रियर डिफ्यूज़र टाइटेनियम ब्लैक मैट में है। संपूर्ण लुक से मेल खाने के लिए रूफ रेल और अलॉय व्हील भी ब्लैक में हैं। ऑडी क्यू7 ब्लैक ऐडिशन के लांच के बाद ऑडी इंडिया कैम्पेन के तहत अपना फेस्टिव सीज़न भी शुरु कर रही है। जो ग्राहक भारत सरकार की 30 प्रतिशत डैप्रिसिएशन स्कीमों का फायदा उठाना चाहते हैं उनके लिए ऑडी इंडिया ने विशेष ऑफर पेश किए हैं जो 30 सितंबर 2019 तक चलेंगे।

Volkswagen I.D 3
इलेक्ट्रिक कार से उठा पर्दा, फुल चार्ज पर चलेगी 550 किमी

नई दिल्ली। एजेंसी

Volkswagen ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ID.3 से पर्दा उठा दिया है। 2019 Frankfurt Motor Show में पेश की गई Volkswagen I.D 3 इलेक्ट्रिक कार तीन वेरियंट में उपलब्ध है। इनमें ID.3 First, ID.3 First Plus और ID.3 First Max शामिल हैं। इनकी रेंज 330 किलोमीटर से 550 किलोमीटर के बीच है। इस इलेक्ट्रिक कार की शुरुआती कीमत 30 हजार यूरो यानी करीब 23.80 लाख रुपये है।

फोक्सवैगन आईडी3 के बेस वेरियंट ID.3 First में 45 kWh की बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज पर 330 किलोमीटर तक चलेगी। ID.3 First Plus वेरियंट 58 kW बैटरी के साथ उपलब्ध है, जिसकी रेंज 420 किलोमीटर है। टॉप वेरियंट ID.3 First Plus में 77 kWh की बैटरी दी गई है और यह फुल चार्ज पर 550 किलोमीटर तक की दूरी तय करेगा। इस हिसाब से भारत में यह कार आने पर इसके टॉप मॉडल को एक बार फुल चार्ज करके बिना रुके आप दिल्ली से लखनऊ की दूरी

(554.7 किमी) तय कर लेंगे। कंपनी का दावा है कि 100 के फास्ट-चार्जर से 30 मिनट चार्ज करने पर यह इलेक्ट्रिक करीब 290 किलोमीटर तक चलेगी।

फोक्सवैगन आईडी3 इलेक्ट्रिक हैबचैक कार है। कॉम्पैक्ट होने के बावजूद इसमें सेगमेंट के हिसाब से पर्याप्त जगह है। कार में एलईडी हेडलाइट्स हैं, जो एक क्रोम स्टिप के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ी हैं। स्ट्रिप के बीच में फोक्सवैगन का नया लोगो दिया गया है। इस इलेक्ट्रिक कार के अंदर किसी दूसरी हैचबैक के मुकाबले ज्यादा जगह है। इसमें 5 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। कार में फुल कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल और 10-इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है।

फोक्सवैगन ने इसका कैबिन काफी हाइ-टेक बनाया है। हेजार्ड लाइट्स और विंडो को छोड़कर बाकी सभी कंट्रोल्स के लिए टच सेंसिटिव बटन दिए गए हैं। कार में आईडी3 ऐप की मदद से स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की भी सुविधा मिलेगी।बेस वेरियंट में नेविगेशन सिस्टम, DAB+ डिजिटल रेडियो, हीटेड सीट्स और 18-इंच के अलॉय वील्ज मिलेंगे। फर्स्ट प्लस वेरियंट में क्रूज कंट्रोल, रियर व्यू कैमरा, की-लेस एंट्री, 2 यूएसबी पोर्ट, ऐम्बिएंट लाइटिंग और 19-इंच के अलॉय वील्ज होंगे। टॉप वेरियंट में हेड्स-अप डिस्प्ले, बीट्स साउंड सिस्टम, पैनोरैमिक सनरूफ और 20-इंच अलॉय वील्ज दिए गए हैं। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में फोक्सवैगन की यह इलेक्ट्रिक कार यूरोप की सड़कों पर दौड़ती नजर आएगी।

सऊदी अरब से हमें तेल की आपूर्ति का पूरा भरोसा है- प्रधान

नयी दिल्ली। एजेंसी

सउदी अरब के नये ऊर्जा मंत्री शहजादा अब्दुल्ल अजिज बिन सलमान ने भारत को आश्वस्त किया है कि उनका देश भारत के लिये कच्चे तेल का विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि सउदी अरब भारत में निवेश के लिये प्रतिबद्ध है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात के दौरान अब्दुल्ल अजिज ने यह आश्वासन दिया। धर्मेन्द्र प्रधान तीन देशों की सरकारी यात्रा पर गए थे । सउदी अरब के नये ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के बाद प्रधान ने ट्वीट कर कहा, ''सउदी अरब के नवनियुक्त ऊर्जा मंत्री एचआरएच प्रिंस अब्दुल्ल अजिज बिन सलमान से जेद्दाह में मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ सउदी ऊर्जा मंत्रालय में पहले हुई मुलाकात की यादें ताजा हुई।'' सउदी अरब के सुलतान सलमान ने पिछले सप्ताह खालिद अल- फलिह को ओपेक के ऊर्जा मंत्री से हटा दिया था और उनके स्थान पर अपने एक बेटे को ऊर्जा मंत्री बना दिया।

गोल्ड ईटीएफ की तरफ निवेशकों का बढ़ा रुझान

मुंबई। आईपीटी नेटवर्क

गोल्ड ईटीएफ (गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में अगस्त में 145 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ है, जो करीब सात साल का रिकॉर्ड है। अगस्त में गोल्ड ईटीएफ की परिसंपत्तियों में 718 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बाजार में अस्थिरता के चलते गोल्ड ईटीएफ फंड से भी निवेशक लगातार पैसे निकाल रहे थे। नवंबर 2018 के बाद अगस्त महीने में गोल्ड ईटीएफ में निवेश देखा गया। बाजार जानकारों का कहना है कि रुपये के कमजोर पडने और सोने की कीमतों में तेजी के बीच गोल्ड ईटीएफ में निवेश बढ़ा है। दिसंबर 2012 के बाद यह गोल्ड ईटीएफ में यह सबसे ऊंचा निवेश है। 2012 में ईटीएफ में 474 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। उसके बाद ईटीएफ निवेश में लगातार गिरावट देखी गई। गोल्ड ईटीएफ में मासिक के साथ-साथ सालाना आधार पर भी वृद्धि देखी गई है। जुलाई में गोल्ड ईटीएफ से 17.66 करोड़ रुपये और अगस्त, 2018 में 45 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने गोल्ड ईटीएफ में 145.29 करोड़ रुपये का शुद्ध निवेश हुआ। नवंबर 2018 में गोल्ड ईटीएफ में 10 करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। इसके बाद दिसंबर 2018 में 25 करोड़ रुपये की निकासी हुई। इस साल जनवरी में 55 करोड़, फरवरी 14 करोड़, मार्च में 38 करोड़, अप्रैल में 10 करोड़, मई में 26 करोड़, जून में 16 करोड़ और जुलाई में 18 करोड़ रुपये की निकासी हुई। नौ महीनों के बाद अगस्त में 145 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इससे पहले गोल्ड ईटीएफ में अक्टूबर 2016 में 20 करोड़ रुपये और मई, 2013 में पांच करोड़ रुपये का निवेश हुआ था। नवीनतम निवेश से अगस्त के अंत तक गोल्ड ईटीएफ के प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां 5,799 करोड़ रुपये हो गईं। गोल्ड ईटीएफ के अधीन परिसंपतियां अगस्त 2013 के बाद सबसे अधिक अगस्त महीने में बढ़ी है। अगस्त में परिसंपत्तियों में 718 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। जुलाई के अंत तक यह 5,080 करोड़ रुपये थी।

अंडमान में 'काले मोती' की खेती को प्रोत्साहन को उद्यमी वैज्ञानिक से हाथ मिलाएगा कृषि संस्थान

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) का अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रकोष्ठ वहां क्षेत्र में समुद्री जल में 'मोती की खेती' पर अनुसंधान कर रहे निजी क्षेत्र के उद्यम मरीन एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज के साथ सहयोग का समझौता करने की संभावना तलाश रहा है। विगत में 'काला पानी' के नाम से चार्चित अंडमान के कुछ तटीय क्षेत्र अपनी पारिस्थितिकी के कारण पर्ल फार्मिंग (मोती की खेती) के लिए काफी उपयुक्त समझे जाते हैं। वैज्ञानिक डॉ. अजय सोनकर के नेतृत्व में उद्यम मरीन एक्वाकल्चर इंडस्ट्रीज पोर्ट ब्लेयर के पास तटीय क्षेत्र में काले मोती की फार्मिंग के अनुसंधान और विकास में लगी है।

डॉ. सोनकर ने से कहा,आईसीएआर के पोर्टब्लेयर स्थिति सेन्ट्रल आइलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टिट्यूट (सीआईएआरआई) ने हमारे साथ सहयोग के प्रस्ताव पर रुचि दिखाई है। यह सहयोग छात्रों, शोधकर्ताओं और मोती की खेती करने के इच्छुक उद्यमियों व किसानों के लिए नयी संभावनायें पैदा करने में मदद करेगा। सीआईएआरआई के कार्यकारी निदेशक डा. ए कुंडू ने कहा, हम पर्ल एक्वाकल्चर (समुद्री मोती की खेती) के क्षेत्र में काम करने वाले जानकारों का एक प्रतिनिधिमंडल डॉ. सोनकर के पास सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, ''हमारे संस्थान की कोशिश है कि अंडमान के विशाल समुद्री संसाधनों का देश हित में उपयोग किया जाये।

पर्ल एक्वाकल्चर के लिए अंडमान की समुद्री परिस्थितियां बेहद अनुकूल हैं। हमें सोनकर के काम की जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने सहयोग देने की मंशा जताई है।'' उन्होंने कहा कि यह सहयोग न सिर्फ हमारे यहां पढ़ रहे देश विदेश के छात्र-छात्राओं को इस क्षेत्र की व्यावहारिक जानकारी प्रदान करेगा बल्कि अंडमान को काला मोती के केन्द्र के रूप में विकसित करने में उत्प्रेरक बनेगा।'' डॉ. कुण्डू ने कहा, ''डॉ. सोनकर द्वारा विकसित किया गया काला मोती दुनिया में अनोखा है।'' उन्होंने कहा, ''हम इस संबंध में संस्थान के अंशधारकों की बैठक करने जा रहे हैं और जल्द ही इस दिशा में डॉ. सोनकर के साथ प्रौद्योगिकी अंतरण के संबंध में करार होने की संभावना है। हमारी बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है।''

मूलतः इलाहाबाद के निवासी अजय सोनकर ने वर्ष 1994 में मीठे पानी में मोती का उत्पादन कर दुनिया भर में भारत को ख्याति दिलाई थी। उन्होंने समुद्री पानी में 'पिंक टाडा मारगरेटीफेरा' प्रजाति के सीप की प्रजाति में दुनिया के सबसे बड़े आकार (22 मिमी) का काला मोती बनाकर पर्ल एक्वाकल्चर के क्षेत्र में जापानियों के प्रौद्योगिकीय एकाधिकार को चुनौती दी और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. अब्दुल कलाम की प्रशंसा पाई। डॉ. सोनकर ने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि ऐसे साझा प्रयास के जरिये देशहित में कुछ किया जाये जो बड़ी संख्या में रोजगार सृजित करेगा। यह भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देने के साथ मोती उत्पादन के क्षेत्र में भारत का नाम ऊंचा करेगा।''

बीते दिनों की बात हो सकते हैं शैंपू-तेल के छोटे प्लास्टिक पाउच

नई दिल्ली। एजेंसी

शैंपू, तेल व अन्य सामग्रियों के छोटे-छोटे प्लास्टिक पाउच जल्द ही बंद हो सकते हैं। एनजीटी में पेश रिपोर्ट में विशेषज्ञ समिति ने महज एक बार इस्तेमाल होने वाले शैंपू, तेल आदि सामग्रियों के प्लास्टिक पाउच को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए समिति ने पानी की छोटी-छोटी प्लास्टिक की बोतलों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया है। समिति ने कहा है कि एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक के पाउच का कूड़ा न सिर्फ उठाने में दिक्कत होती है बल्कि इसके उचित निपटारे में भी परेशानी होती है। समिति ने इसकी जगह बायो-प्लास्टिक और पॉली लैक्टिक से बने बायो-डिग्रेडबल प्लास्टिक के इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है।

मई में गठित की गई थी समिति

एनजीटी ने हिम जागृति वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर मई में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अगुवाई में विशेषज्ञ

समिति का गठन किया था। ट्रिब्यूनल ने समिति को देशभर में हो रहे प्लास्टिक के अत्याधिक इस्तेमाल पर अपना सुझाव और इसके नियमन के उपाय बताने के लिए कहा था। समिति ने जून, जुलाई व अगस्त माह में खाने-पीने से लेकर सौंदर्य प्रसाधन, दवाइयां, कपड़े आदि बनाने वाली राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के कई प्रतिनिधियों के अलावा पर्यावरण विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों के साथ कई दौर की बैठकों बाद रिपोर्ट तैयार करके एनजीटी में पेश किया है।

नियमन की जरूरत

समिति ने कहा है कि देश में प्लास्टिक के अत्याधिक इस्तेमाल पर रोक लगाने और इसके नियमन की जरूरत है। रिपोर्ट में प्लास्टिक कचरे का निपटारा तय नियमों के अनुसार प्रभावी तरीके से करने का सुझाव दिया गया है।

प्रोत्साहन व दंड लगाने का सुझाव

विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सभी क्षेत्र की कंपनियों को अपने सामानों की पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव कर प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना चाहिए। सरकार व अन्य संबंधित निकायों को उन कंपनियों को प्रोत्साहन देने को सुझाव दिया है जो नए तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करते हैं। दूसरी तरफ पैकेजिंग में अत्याधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वालों पर दंड लगाने का भी सुझाव दिया है।

बांस से बने उत्पादों के इस्तेमाल को बढ़ावा

समिति ने प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने और इसके विकल्प और पर्यावरण हितैषी चीजों को बढ़ावा देने की वकालत की है। विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में बांस व लकड़ी से बने बर्तनों और पत्तियों से बनी प्लेट व दोनों का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। इसके अलावा जूट व कपड़े के थैले प्रयोग करने का सुझाव दिया है। यहां सबसे ज्यादा प्रयोग विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन और दवाइयों के अलावा कपड़ों की पैकेजिंग में प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल होता है।

NPCI के नए नियम ई-वॉलिट कंपनियों को लग सकता है बड़ा झटका

नई दिल्ली। एजेंसी

यूपीआई के बूते सफलता हासिल करने वाली फोनपे और गूगलपे जैसी कंपनियों को अब झटका लगने वाला है, क्योंकि नैशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने डिजिटल पेमेंट कंपनियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कई तरह की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यूपीआई में जोखिमों को कम किया जा सके। ञ्ण्ष्ट द्वारा लागू महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक में डिजिटल पेमेंट कंपनियों की यूपीआई बाजार हिस्सेदारी की सीमा निर्धारित की गई है।

इस कदम से सीधे तौर से यूपीआई-ओनली कंपनियों को नुकसान होगा, जिसमें वॉलमार्ट का फोनपे और गूगल पे के साथ ही जल्द लॉन्च होनेवाली वॉट्सएप पे भी शामिल है। दिलचस्प है कि पेटीएम इकलौती बड़ी कंपनी है, जो यूपीआई के अलावा अपने वॉलेट और कार्ड्स का समर्थन कर रही है। अप्रैल 2020 से फोनपे और गूगलपे को अपनी बाजार हिस्सेदारी 33 फीसदी तक की सीमा में ही रखनी होगी, जिससे अंततः उनकी विकास योजनाओं में रुकावट आएगी।

सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने के लिए इन कंपनियों ने अब तक काफी ज्यादा निवेश किया है, और यह कदम उनके लिए एक बड़ा झटका है। दिलचस्प है कि मॉर्गन स्टेलने ने हाल ही में वॉलमार्ट के शेयर कीमतों में वृद्धि के लिए फोनपे की सफलता को बड़ा श्रेय दिया था। लेकिन सीमा तय करने की नई नीति से कंपनी के मूल्यांकन और वित्त जुटाने की योजनाओं को भी झटका लगेगा, क्योंकि वह टाइगर ग्लोबल, टेंसेंट, डीएसटी ग्लोबल, सॉफ्टबैंक और अन्य से 1 अरब डॉलर जुटाने की प्रक्रिया में है।

एक वरिष्ठ बैंकर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर कहा, 'यह गैर-बैंकिंग भुगतान कंपनियों द्वारा बढ़ते सुरक्षा खतरों पर एनसीपीआई की चिन्ताओं को दिखाता है। अब फोनपे को वित्त जुटाने की व्यवसायिक रणनीति पर पुर्नविचार करना होगा।' वहीं, उद्योग के अन्य दिग्गजों और विशेषज्ञों ने एनपीसीआई के इस कदम की सराहना की है और उनकी राय है कि इससे भारत में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे को सुरक्षित किया जा सकेगा।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुनः प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।